5

सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे प्रभात जी

7

समसामयिक आलेखः शादियों पर दिखावा बंद हो

8

आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे ...

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 14 प्रति सोमवार, 29 जुलाई 2024 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के समर्थन से सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हुआ और 26 जुलाई को समाप्त भी हो गया है। मानसून सत्र में विपक्षी कांग्रेस कानून-व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा कि वह बिगड़ती कानून व्यवस्था खासकर पिछले महीने बलौदाबाजार शहर में हुई हिंसा के विरोध में राज्य विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया है। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में कुल पांच बैठकें हुई। कुल मिलाकर जिस तरह से विधानसभा का संचालन हुआ और विपक्षी दलों के नेताओं को नरम ढंग से भाजपा नेताओं ने जबाव दिया उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ विष्णुदेव साय सरकार का संचालन हो रहा है। इसका एक बड़ा संकेत इस ओर भी इशारा करता है कि विष्णुदेव साय सरकार ने अब तक बघेल सरकार के दौरान हुए घोटालों के मुख्य आरोपियों को कोई सजा नहीं दिलवाई और न ही उन पर फिलहाल कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है।

हंगामेदार रहा विस का मानसून सत्र

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने किया ये दावा

प्रदेश कांगेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि राज्य में सात महीनों में रेप के 300 मामले, गैंगरेप की 80 घटनाएं और 200 से अधिक हत्याएं दर्ज की गईं। उन्होंने दावा किया कि चाकूबाजी, लूटपाट, डकैती और झपटमारी की अनगिनत घटनाएं हुई हैं। बीजेपी आम आदमी की रक्षा करने में विफल रही है। बैज ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत किया था, जबकि बीजेपी सरकार ने महज सात महीनों में इसे बर्बाद कर दिया है।

बीजापुर मुठभेड़ मामले पर जमकर बवाल

बीजापुर मुठभेड़ मामले पर मुख्य विपक्षी दल ने हंगामा किया। कांग्रेस के सदस्यों ने मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि मारे गए ज्यादातर लोग नक्सली नहीं बल्कि निर्दोष ग्रामीण थे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल को नक्सलियों का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। प्रश्नकाल में विपक्षी नेता चरणदास महंत ने पिछले वर्ष दिसंबर से इस वर्ष जून के बीच राज्य में नक्सली घटनाओं का आंकड़ा मांगा। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जवाब में कहा कि 273 नक्सली घटनाओं में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 92 मुठभेड़ शामिल हैं। बता दें कि शर्मा गृह विभाग का प्रभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा, "दिसंबर (2023) से इस साल जून के बीच नक्सली घटनाओं और मुठभेड़ में 19 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 88 जवान घायल हुए जबकि 34 माओवादियों को मार गिराया गया।

अनेक मुददों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

सदन में गूंजा बीजापुर मुठभेड़ का मामला

शर्मा ने सदन को बताया कि राज्य में 137 नक्सली मारे गए और 171 को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस साल 30 जून तक 790 नक्सलियों को जेल में डाला गया। 765 पर मुकदमा जारी है और 25 को दोषी ठहराया गया है। पूर्वमंत्री कवासी लखमा और विक्रम मंडावी समेत कांग्रेस विधायकों ने पीडिया गांव के करीब इस वर्ष मई माह में हुई मुठभेड़ की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि तेंदूपत्ता संग्रह में लगे निर्दोष ग्रामीणों को पुलिस ने मार डाला।

ज्यादातर निर्दोष ग्रामीण मारे गये- कांग्रेस

उपमुख्यमंत्री ने आरोपों पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नक्सलियों का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को नक्सलियों के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए।

अंतिम दिन गूंजा पीडीएस का मामला

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में राशन दुकान की गड़बड़ी का मामला गूंजा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक इस मामले को लेकर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से सवाल पूछे। प्रश्नकाल के दौरान विधायक कवासी लखमा ने पूछा कि सुकमा जिले में कई पीडीएस दुकानें किराए पर चल रहे हैं। सरकार की ओर से किराए का कितना भुगतान किया जाता है। इस सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने कहा कि सुकमा जिले में 192 दुकान संचालित है। 175 के पास भवन है। 16 दुकानें किराए पर संचालित है। इस दौरान पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने पीडीएस दुकान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि, सुकमा में पीडीएस दुकान बस्ती से हटाकर पहुंच विहीन क्षेत्र में भेजी जा रही है। राशन के गबन के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अंदर नक्सली के डर से कोई नहीं जाएगा और अधिकारी पीडीएस दुकानों का राशन खाएंगे।

कांग्रेस के विधायक वेल में घुसे, 30 सदस्य निलंबित

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इसे गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने ठुकरा दिया। तब कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत कांग्रेस के 30 विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। नियमानुसार वेल में प्रवेश पर सदस्य स्वतः निलंबित हो जाएंगे। इस कारण ये सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए। महंत ने कहा कि प्रदेश की समरसता को खत्म करने का षडयंत्र हुआ है। अब तक अलग-अलग संगठनों के 168 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। ऐसे में सदन में चर्चा की जा सकती है या नहीं?

पहला अनुपूरक 7329 करोड़ का, इसमें 2 तिहाई महतारी वंदन के लिए मांगे

सत्र के पहले दिन साय सरकार ने पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 7329 करोड़ रुपए की मांग की है। इसमें से 4900 करोड़ यानी दो तिहाई राशि महतारी वंदन योजना के लिए मांगी है। योजना में प्रदेश की महिलाओं को हर माह 1000 रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी राशि रखी गई है।

एक माँ की खुशी के आँसू ने कौशल विकास के महत्व को साक्षात किया

-अमित राय

जगत प्रवाह. कोलकाता। खुशी के पैमाने की कोई सीमा न थी। एक माँ की खुशी के आँसू हर एक शब्द पर अनमोल मोतियों की तरह टपक रहे थे। माँ अपनी बेटी को साथ लिए अपने हृदय से निकल रहे शब्दों का भाव प्रदर्शन कर रही थी। शब्द-दर-शब्द बढ़ते रहे और आँसुओं के बूंदों की रफ्तार भी बढ़ती गई। एक पल ऐसा भी आया कि शब्द तो विराम हो गए पर खुशी के भाव को आँसुओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण बना डाला। निःशब्द आँसू बहुत कुछ समझा गए। हावड़ा के बेलूर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित "भोट बगान ऊर्दू गर्ल्स हाई स्कूल" में आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान इस पल का मैं गवाह बना और एक माँ की खुशी के आँसू ने कौशल विकास के महत्व को साक्षात किया। कौशल विकास क्रम को पूरा करने पर बेटी की नौकरी लगी। जिससे परिवार को आर्थिक सहारा मिला व जीवन में सकारात्मक बदलाव हुए और आज खुशियाँ उनके साथ है। माँ ने इसका श्रेय हावड़ा नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रेयाज अहमद को दे डाला। बता दें कि हावड़ा नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रेयाज अहमद की सराहनीय कोशिश, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड के "एकलव्य" पहल के अंतर्गत वर्ष 2022 से भोट बगान ऊर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारंभ हुआ जिसमें "रिटेल" (परचून) और "सिलाई" (गारमेंट्स) से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते है और क्रम पूरा होने पर प्रमाणपत्र भी दिया जाता है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में लगभग 280 छात्र-छात्राओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा किया और इनमें से अनेकों ने नौकरियाँ पाई और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार, समाज, राज्य और देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। मंगलवार 23 जुलाई, 2024 को भोट बगान ऊर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के परिसर में हुए कार्यक्रम दौरान अतिथियों का सम्मान अंगवस्त्र प्रदान कर किया गया। साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण पश्चात नौकरी प्राप्त छात्र-छात्राओं का सम्मान अंगवस्त्र व उपहार देकर किया गया। वहीं 2023-24 वर्ग के लगभग 150 छात्र-छात्राओं को कौशल विकास प्रशिक्षण सम्पन्न करने पर प्रमाणपत्र दिया गया। इस विशेष अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार शब्बीर अहमद, पत्रकार आलमगीर अहमद, सीईएससी के पदाधिकारीगण, बेलूर थाना के पदाधिकारीगण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही अभिभावकगण, छात्र और छात्राएं अधिक मात्रा में उपस्थित रहे।

राजस्व की टीम पर हमला, वाहन में की तोड़फोड़

-समीर शास्त्री

जगत प्रवाह. राजगढ़। जमीन का सीमांकन करने के लिए पहुंची राजस्व की टीम पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया। जिसमें एक आरआइ सहित पटवारियों को चोटें आई हैं। साथ ही पटवारी की कार में भी तोड़फोड़ कर दी। पथराव करते हुए हमलावार मौके से भाग गए। इसके बाद घायल राजस्व टीम को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद पुलिस ने घायल आरआइ की शिकायत पर पांच नामजद सहित 15 अन्य के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। पुलिस अब आरोपितों की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक नाईपुरिया-जोड़क्या गांव में 160 बीघा जमीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकारियों ने एक आरआइ सहित आठ पटवारियों की टीम को जमीन का सीमांकन करने के लिए भेजा था। राजस्व की टीम जैसे ही संबंधित जमीन के समीप पहुंची तो वहां मौजूद 8-10 लोगों ने टीम पर हथियारों से हमला कर दिया। लटठ, तलवारों व पथराव के साथ किए गए हमले में आरआइ राजेंद्र सुमन को गंभीर चोट आई है। साथ ही कुछ अन्य पटवारियों को भी चोटें आई हैं। हमलावरों ने पटवारी की उस गाड़ी को भी फोड़ दिया जिससे राजस्व विभाग की टीम सीमांकन करने पहुंची थी। पीछे से पहुंची पुलिस की गाड़ियों को देखकर हमलावर मौके से भाग निकले। (जगत फीचर्स)

जिला बदर आरोपी को गिरफ्तार कर पहुँचाया जेल

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। 18 जुलाई को मुखबिर द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति के होने की सूचना प्राप्त होने पर रवाना होकर कंग मैरिज गार्डन के पास यात्री प्रतीक्षालय अटारी खेजड़ा पहुंचकर उक्त संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम मिलन पता लाल सिंह उम्र 25 साल निवासी ग्राम पाडोछा थाना कुरवाई का होना बताया, जिसके संबंध में थाना कुरवाई से जानकारी प्राप्त करने पर कलेक्टर विदिशा के आदेश दिनांक 30.04.24 को जिला विदिशा व जिले के सीमावर्ती जिलों से एक बर्ष के लिए निष्कासित करना बताया उक्त आरोपी को उसे गिरफ्तारी का कारण बताते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय विदिशा के समक्ष पेश किया गया। इसमें विशेष भूमिका निरीक्षक सीमा राय, सउनि धर्मजीत गौतम, सउनि शैलेन्द्र सिंह, इरफान अहमद की रही। (जगत फीचर्स)

रीवा में जिंदा महिलाओं को दफनाने के प्रयास से महिला कांग्रेस में आक्रोश

महिला कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. अशोकनगर। अशोकनगर प्रदेश के रीवा में जमीनी विवाद को लेकर दो महिलाओं को जिंदा दफनाने का प्रयास किया गया है। इस घटना के विरोध में जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में उग्र प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, महिला जिला अध्यक्ष डॉ. सीमा सुराणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें प्रदेश में हो रहे महिला अत्याचारों के खिलाफ बढ़ता महिला कांग्रेस का आक्रोश, रीवा में दो महिलाओं को जिंदा मुराम में दबाने संबंधित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

महिला अत्याचार और अपराध में अग्रणी बना मप्र- महिला कांग्रेस

जिला अध्यक्ष सीमा सुराणा ने कहा कि जिले में कुछ समय पहले एक महिला यातायात प्रभारी के साथ भी ऑन ड्यूटी बदसलूकी की गई। जिस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं कि प्रदेश में महिलाओं का निरंतर अपमान और अत्याचार का गढ़ बन गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में जबसे भाजपा की सरकार अस्तित्व में आई है तबसे प्रदेश महिला अपराधों के मामलों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। महिलाओं पर अत्याचार और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिनपर अंकुश लगाने में तत्कालीन शिवराज सरकार और वर्तमान डॉ. मोहन यादव सरकार नाकाम रही हैं। सरकार को चेतावनी दी कि अब महिलाओं पर अत्याचार के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथी वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में महिला जिला अध्यक्ष डॉ. सीमा सुराणा के साथ जिला महामंत्री अलीना राय जिला उपाध्यक्ष विमलेश शर्मा ग्रामीण जिला ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी प्रजापति शहरी ब्लॉक अध्यक्ष नीलू खान रुखसाना बानो, ममता कोठारी रानी नामदेव, महासचिव किरण बाई, मुमताज, अख्तरी बानो, प्रेमा बाई, शबनम खान आरती कौशल, गायत्री बाई ,प्रीति परिहार, गुड्डीबाई, मालती बाई, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। (जगत फीचर्स)

आखिर कब मिलेगा इंसाफ, चरमरा रही शिक्षा व्यवस्था

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। शिक्षामंत्री के ग्रह जिला के लिए जूनियर प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी जोड़-तोड़ और सभी नियमों को प्रशासन को ठेंगा बताते हुए अपनी जागीर समझकर जिले के शिक्षा विभाग का संचालन कर रहे हैं। सीनियर प्राचार्य जिनके आदेश जिला शिक्षा अधिकारी का हुआ रातों रात निरस्त अपने आकाओं के माध्यम से निश्चित सीनियर प्राचार्य लोगों में निराश घर कर गई है। जिला शिक्षा अधिकारी के पास 01 वर्ष में करोड़ों रुपये खर्च के लिए माध्यमिक शिक्षा मिशन में आते हैं, माध्यमिक शिक्षा मिशन अभियान के प्रभारी और जिला शिक्षा अधिकारी भी प्रभारी के रूप में हैं फिर दोनों हाथो लड्डू हैं। माध्यमिक शिक्षा मिशन की जो राशि हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों को जिला को विज्ञान और कम्प्यूटर सेंटरों के लिए आती हैं उसका एडिट हर 6 माह में किया जाता है। इनका जरिया है रेडक्रास फण्ड, स्काउट गाईड फण्ड और साथ में शिक्षकों के जीपीएफ निकलने के 4 प्रतिशत लिए जाते हैं। शिक्षक लोगों के लिए बेटे बेटियों की शादी और मकान या बीमारी के लिए रुपये चाहिए तो 4 प्रतिशत दो और स्वीकृति आदेश राशि अंकित सहित जारी कर दिया जाता। नहीं देने पर तमाम आपत्ति लगाकर प्रकरण वापिस कर दिया जाता है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को जिले की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा रहीं हैं, प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावक लोगों का शोषण आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की और सरकारी स्कूलों में डेढ़ महा बीत जाने के बाद भी अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के आदेश जारी नहीं किया है।

(जगत फीचर्स)

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत नर्मदापुरम रावत द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में आत्म निर्भर पंचायत, समृद्ध मध्य प्रदेश विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती की उपयोगिता एवं इससे आदिवासी अंचल की स्वासहायता समूह की दीदियों को हुए लाभ को बताया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में तीन जिलों को ही मिला प्रस्तुतीकरण का अवसर जिसमें सीईओ जिला पंचायत नर्मदापुरम सौजान सिंह रावत द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। रावत ने बताया कि नर्मदापुरम जिले में कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीना के मार्गदर्शन में की जा रही है प्राकृतिक सब्जी की पैदावार। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम सोजान सिंह रावत द्वारा ''फार्म टू किचिन'' विषय पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री एन्दल सिंह कंसाना, कैलाश विजयवर्गीय, कुंअर विजय शाह आदि द्वारा सहभागिता की गयी। विशेष बात यह है कि राज्य स्तर पर मात्र तीन जिलों भोपाल, ग्वालियर एवं नर्मदापुरम को प्रस्तुतीकरण दिये जाने का अवसर प्रदान किया गया।सीईओ जिला पंचायत श्री रावत द्वारा विषय के रूप में आदिवासी विकास खंड केसला जो कि कुपोषण हेतु चिन्हांकित भी है, में ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जा रहे प्राकृतिक खेती को चुना गया था। सीईओ जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि किस प्रकार 34 स्व सहायता समूहों के 102 महिला सदस्यों द्वारा 72 एकड में प्राकृतिक खेती करके न केवल उत्पादन की लागत को कम किया है बल्कि अपनी आर्थिक उन्नति भी की है। किस प्रकार महिलाओं का चयन, स्थल का चयन, सब्जी की प्रजातियों का चयन किया गया, उन्नत प्रशिक्षण महिलाओं को प्रदान किया गया, उत्पाद के सही विक्रय हेतु मार्केट लिंकेज कैसे संभव हुआ आदि का विस्तृत ब्यौरा सीईओ जिला पंचायत द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। साथ ही बताया गया कि प्राकृतिक खेती राशायनिक खेती से किस तरह उन्नत एवं फायदेमंद है एवं उन महिलाओं के भी उदाहरण प्रस्तुत किये गये जिनके द्वारा यह कार्य किया गया है।जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किये जा रहे उक्त कार्य के विषय में जानकारी दी गयी 'फार्म टू किचिन'' अवधारणा में ग्रीन एन्ड ग्रेन्स संस्था द्वारा किये गये सहयोग का उल्लेख करते हुए बताया गया कि संस्था के सहयोग एवं ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों की मेहनत एवं जिला स्तर पर किये गये शासकीय प्रयासों के माध्यम से किसानों की वार्षिक आय में 70 हजार से 01 लाख रूपये प्रतिवर्ष की वृध्दि सुनिश्चित हुई है। टमाटर एवं बैगन प्रसंस्करण के लिए सोलर ट्रायल की सुविधा उपलब्धय कराई जा रही है, भविष्य की कार्ययोजना बताते हुए अवगत कराया गया कि समूहों को सशक्त बनाने हेतु - माइक्रो-प्रोसेसिंग इकाइयाँ, दाल मिल, मसाला इकाई, बाजरा पोहा और बहुत कुछ को शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश के 55 जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

84 दिन चले कारगिल युद्ध के हुए 25 वर्ष

1999 में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की विजय का प्रतीक है। कारगिल युद्ध जम्मू-कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में मई से जुलाई 1999 के बीच हुआ था। साल 1999 के शुरुआत में ही पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर हमारे भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर गए और कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। 84 दिन चले इस युद्ध को आज भले 25 साल हो गए हैं लेकिन सेनाओं के वीरता की कहानी आज भी याद की जाती है। क्षेत्रीय लोगों ने भारतीय सेना को घुसपैठियों की सूचना दी, जब पेट्रोलिंग के लिए वाहन सेवा के कुछ जवान भेजे गए तो घुसपैठियों ने पांच जवानों को शहीद कर दिया। 10 मई, 1999 को द्रास, काकसर, बटालिक सहित कई सेक्टर में करीब 800 पाकिस्तानी घुसपैठियों के घुसने की सूचना मिली। उसके बाद ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों के क्षेत्र में बमबारी की। 27 मई को पाकिस्तानी सेना ने दो भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट के. नचिकेता को बंदी बना लिया गया और स्क्वॉड्रन लीडर अजय अहूजा शहीद हो गए। इसके बाद देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने घोषणा कर दी की कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने लगातार 11 घंटे लड़ाई कर टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराया। उसके अगले ही दिन द्रास सेक्टर पर भी हमारा कब्जा हो गया। और दो दिन बाद 7 जुलाई को बाटलिक सेक्टर में जुबर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने फिर कब्जा जमाया लेकिन इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। 11 जुलाई को भारतीय सेना ने बाटलिक सेक्टर की सभी पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा जमाया जिसके बाद 12 जुलाई को पाकिस्तान के तात्कालिक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की। 14 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को देश से पूरी तरह से खदेड़ दिया और फिर 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध को जीतने की घोषणा कर दी।

सियासी गहमागहमी

कलमनाथ को मिल सकती है प्रदेश में प्रमुख जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेताओं में चल रही आपसी अंतर्कलह के संकेत पार्टी आलाकमान तक पहुंच गये हैं। कई बार समझाइश देने के बाद भी जब पार्टी नेताओं में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो अब इस बात की चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि प्रदेश के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिये प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रमुख जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर उच्च स्तरीय समिति में सहमति भी बन गई है। उम्मीद है कि अगले एक दो महीने में कमलनाथ को पार्टी राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर बिखरती हुई प्रतीत हो रही कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने का जिम्मा दे सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर कमलनाथ को यह जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित ही इससे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कद नीचे हो जाएगा।

क्या शिवराज की राह पर चल पड़े हैं मोहन?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार प्रदेश में विकास और निवेश को लेकर चिंतित हैं। यही कारण है कि वे निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नवाचार करते हुए रीजनल स्तर पर इनवेस्टर समिट का आयोजन किया गया। जबलपुर में हुए इस समिट में निवेशकों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। मोहन यादव की बढ़ते कार्ययोजना को लेकर तथाकथित शिवराज समर्थकों ने यह कहना आरंभ कर दिया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के पद चिन्हों पर चलकर कार्य कर रहे हैं। जबकि उन्हें खुद अपना एक अलग रास्ता और मुकाम तैयार करना चाहिए जिससे वे प्रदेश को एक नई पहचान दिला सके। अब समझने वाली बात यह है कि क्या सच में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान का रास्ता अपनाया हुआ है या फिर वे कुछ नया करने की राह पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को कारगिल विजय दिवस पर मेरा शत्-शत् नमन।

उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव ऋणी रहेगा।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता श्री प्रभात झा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ।

ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

विनम्र श्रृद्धांजलि : सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे प्रभात जी

विजया पाठक/जगत प्रवाह

पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा का असामयिक निधन संपूर्ण पत्रकारिता समाज के लिये बड़ा दुःखद का विषय है। प्रभात जी बेहद सरल और सौम्य व्यक्तित्व के नेता थे। चूंकि वे खुद एक पत्रकार रहे हैं। इसलिये पत्रकारों की परेशानियों, उनके जीवन के संघर्ष को करीब से जानते थे। प्रभात जी मेरे पति जगत पाठक जी के बेहद करीबी मित्रों में से एक थे। यही कारण था कि उनका कई बार हमारे घर आना हुआ करता था। इस दौरान प्रभात जी ने राजनैतिक विषयों के इतर केवल पारिवारिक विषयों पर ही ध्यान दिया। खास बात यह है कि प्रभात जी जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने तभी भारतीय जनता पार्टी से मीडिया और पत्रकारों का जुड़ाव आरंभ हुआ। वैसे तो मेरा उनसे परिचय पुराना रहा है लेकिन जब वह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने तो मेरा उनसे काफी मिलना-जुलना हुआ। अनेक बार गंभीर विषयों पर चर्चाएं हुई। जब भी उनको समय मिलता वह फोन लगा लिया करते थे। पत्रकारिता पेशे से होने के कारण वह पत्रकारों का काफी सम्मान करते थे। लगभग सभी पत्रकारों से अच्छे से मिलते थे। और पत्रकारों की बातों पर गौर करते थे। इससे पहले तो भाजपा नाममात्र ही पत्रकारों से बात किया करती थी। इसके अलावा उन्हें लिखने पढ़ने का भी काफी शौक था। उस समय उनके आलेख काफी छपते थे। जो दिशा देने वाले होते थे। कहते हैं, पत्रकार के संपर्क का दायरा तो होता है, पर प्रेम से नहीं, डर के कारण। ग्वालियर में तब बीच में कुछ समय के लिए प्रदीप पंडित कार्यकारी संपादक थे। प्रभात जी से उन्होंने पूछा, आप रिपोर्टर हो, गाड़ी आपको चलाना चाहिए। प्रभात जी ने कहा, रिपोर्टर हूँ, ड्राइवर नहीं। जहां खड़ा होता हूँ, गाड़ी रुक जाती है, भाजपा के बड़े नेता और सांसद के नाते तो यह सुविधा काफ़ी बाद में उनके भविष्य में छिपी थीं। पर मैंने देखा है, लोग अपने गंतव्य की दिशा बदल कर भी उनको उनके गंतव्य तक छोड़ने में ख़ुशी अनुभव करते थे। न केवल ग्वालियर, यह तो उनकी प्रारंभिक कर्म भूमि रही, पर वह जहाँ भी जाते थे, पूरे परिवार को अपना बना लेते थे। शाम को उनकी टेबल पर अक्सर इतने घरों से खाने के डिब्बे आते थे कि हम देखकर दंग हो जाते थे, पत्रकारिता के सूत्र इस प्रकार की सुई भी गिरती थी तो प्रभात जी को खबर रहती थी।

क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या वामपंथी, प्रभात जी सबकी खबर ले भी लेते थे, पर व्यक्तिगत संबंध उतने ही मधुर। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हों या उसी कार्यालय का भृत्य, प्रभात जी उसके हैं यह विश्वास उन्होंने कमाया। लक्ष्मी पुत्रों से भी उनके संबंध चूल्हे तक थे, पर मजाल प्रभात जी की कलम कभी बिकी हो इसका आरोप तो दूर किसी ने चर्चा भी की हो। ऐसे थे, प्रभात जी, ऐसे थे हम सब के भाईसाहब।

प्रभात जी का परिचय भाजपा के सांसद के रूप में भी दिया जाएगा। उनको प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रूप में भी याद किया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनके अखिल भारतीय प्रवास के योगदान को रेखांकित किया ही जाएगा। कांग्रेस शासनकाल में जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी, तब "संवाद प्रमुख" के पद को अत्यंत महत्वपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, इसकी भी एक कहानी है और उनके संपादक के कार्यकाल के नाते "कमल संदेश" ने कितने प्रभावी संदेश दिये वह भी एक प्रेरक कहानी हैं। ऐसे विनम्र और महान व्यक्तित्व के धनी स्व. प्रभात झा जी को मेरी ओर से श्रद्धाजलि...।

बाढ़ का इंतजार नही, इंतजाम जरूरी है

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद्

जगत प्रवाह. भोपाल। बाढ़ ने इस वर्ष भी अपना विकराल रूप दिखाया है। हाल ही में असम, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भयानक बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है, सैकड़ों की जान ली है और लाखों की संपत्ति को नष्ट कर दिया है। पूर्वोत्तर की बात करें तो असम में जहां लगभग 23 लाख लोग प्रभावित हैं वहीं मणिपुर व नागालैंड भी इसकी चपेट में है। जबकि सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम में भी भारी बारिश हो रही है। पूरे उत्तर भारत में भी भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि बिहार में भारी बारिश के कारण केवल 18 दिनों में बिहार में 12 पुल धराशाई हो गए हैं। बिहार, यूपी और असम में हर वर्ष बाढ़ आता है। हर वर्ष रोकने के लिए इंतजाम किए जाते रहे हैं लेकिन शायद नाकाफी है। 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अनुमान लगाया था कि 21वीं सदी के शुरुआती दशक तक चार करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ के चपेट में होगी। इसे देखते हुए बहुद्देशीय बांध और 35000 किमी तटबंध बनाए गए। लेकिन कम होने के बजाय यह और बढ़ता ही जा रहा है। पर क्या हम हर बार की तरह सिर्फ इसका इंतजार करेंगे या इस बार कुछ ठोस इंतजाम करेंगे?

बाढ़ के कारणों को समझना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार, बाढ़ का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और नदियों के किनारे अवैध निर्माण है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2019 के बीच बाढ़ की घटनाएं 134% बढ़ी हैं। इससे साफ है कि हम सिर्फ प्राकृति के गर्जनाओं का सामना नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही गलतियों का भी खामियाजा भुगत रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सरकारों ने बाढ़ से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। परंतु इनमें से अधिकतर योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। नदियों की सफाई, तटबंधों का निर्माण और जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी जैसे कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप, हर साल बाढ़ के चलते जान-माल का भारी नुकसान होता है। बाढ़ का एक कारण अंतराष्ट्रीय परिस्थिति भी है। नेपाल के कारण बिहार और चीन के कारण असम में बाढ़ आता है। बिहार की अलग समस्या है। उत्तर में नेपाल से तो दक्षिण में झारखंड से और यूपी के ढलान से आए पानी से बिहार में बाढ़ आता है।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के अनुसार, 2015 से 2020 के बीच भारत में बाढ़ के कारण लगभग 1700 लोगों की मौत हुई और लगभग 65 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा। यह

आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि हमारी तैयारियों में कमी है। बाढ़ से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है नदियों के किनारे अवैध निर्माण को रोकना। इसके अलावा, जलभराव वाले क्षेत्रों की नियमित सफाई और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना भी जरूरी है।अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वैज्ञानिकों और जलवायु विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान देना और उन्हें योजनाओं में शामिल करना अति आवश्यक है। साथ ही, बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र को भी सुधारने की जरूरत है ताकि लोगों को समय रहते चेतावनी मिल सके। इसके अलावा, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कचरा फेंकने और नदियों को प्रदूषित करने से बचना होगा। हमें समझना होगा कि नदियों का संरक्षण ही हमारा संरक्षण है।

केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा। हाल ही में, एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, परंतु इनमें से अधिकांश राशि का सही उपयोग नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों के साथ मिलकर जल संसाधन प्रबंधन पर काम करना चाहिए। इससे बाढ़ नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी। बाढ़ के समय राहत कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए स्थानीय प्रशासन को भी तैयार रहना चाहिए। रेस्क्यू टीमें, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री को पहले से ही तैयार रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।

बाढ़ का इंतजार नहीं, इंतजाम जरूरी है। हमें बाढ़ से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना होगा। सिर्फ योजनाएं बनाना और कागजों पर काम करना काफी नहीं है। हमें धरातल पर उतरकर काम करना होगा। तभी हम बाढ़ के प्रकोप से खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। बाढ़ का सामना करना हमारे लिए एक चुनौती है, परंतु सही कदम उठाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। यह समय है जागरूक होने का, संगठित होने का, और मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना करने का। हमारा छोटा सा प्रयास भी बाढ़ से बड़ी राहत दिला सकता है।

(जगत फीचर्स)

स्वतंत्रता को अपनी आंतरिक चेतना का हिस्सा कैसे बनाएं!

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

जगत प्रवाह. भोपाल। कुछ ही दिन बाद देश की आजादी का पर्व 15 अगस्त आने वाला है। यह पर्व पूरे देश में बड़े ही गर्व के साथ मनाया जाता है। हमें वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को यह सिखाना चाहिए कि इस स्वतंत्रता को अपनी आंतरिक चेतना का हिस्सा कैसे बनाएं। कैसे स्वतंत्र चेतना बनें। कैसे अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने वांग्मय को लेकर गौरव का अनुभव करें। अपने समृद्ध इतिहास को तलाशने का प्रयास करें और विस्मृत की गई ऐतिहासिक विभूतियों को अपना आदर्श बनाने की कोशिश करें। अगर चेतना के स्तर पर जाकर देखें तो भारतवर्ष कभी परतंत्र रहा ही नहीं। आक्रांताओं ने भारतवर्ष पर आक्रमण करके इस पर कुछ वर्ष तक शासन अवश्य किया, किंतु भारत की स्वतंत्र चेतना को नष्ट करने में सफल नहीं हो सके। यही कारण है कि भारत अपने स्वतंत्रता के मूल्यों को तमाम विरोधाभासों के बावजूद संजोने में कामयाब रहा, बल्कि भारत का एक बड़ा भू-भाग उस सांस्कृतिक एकता को भी कायम रखने में कामयाब रहा जो भारत की मूल अवधारणा से विकसित हुई थी। हमें बच्चों को यह बताने की आवश्यकता है कि हमारी वैदिक परंपरा से लेकर वर्तमान परंपरा तक स्वतंत्रता का हर जगह सम्मान किया गया। केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे की स्वतंत्रता को भी हमने उतना ही महत्व दिया। यही कारण है कि भारत में सभी समाज और सभी वर्ग फले-फूले। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हर वर्ग के राजा-महाराजा और सामंत हुए। 3000 वर्ष के इतिहास में भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हूण, कुषाण, तैमूर, तातार, मुगल, अंग्रेज जैसे आक्रांता इस देश पर समय-समय पर आक्रमण अवश्य करते रहे लेकिन भारत अपनी आंतरिक स्वतंत्र चेतना के कारण इनसे अप्रभावित रहा, बल्कि भारत भूमि के जिन निवासियों ने आक्रांताओं की धार्मिक परंपराओं को अपनाया। उन्होंने भी भारत की संस्कृति को नहीं त्यागा। अतिथि उनके लिए भी देवता ही रहा। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को उन्होंने भी अपनाया। और यही उनकी स्वतंत्र चेतना थी। हमें एक नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का बोध होना बहुत आवश्यक है। हमें राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी परिलक्षित होती है कानून का पालन करने से, ईमानदारी बरतने से और मेहनत और लगन से काम करने से। विशेष बात यह है कि यह सारे गुण हमारे भारतीय वांग्मय में और हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं, इसलिए जब हम कर्मण्येवाधिकारस्ते के सिद्धांत का पालन करते हैं, तब राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध स्वतः ही हो जाता है। यदि हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपनाते हैं तो राष्ट्र के हर निवासी के प्रति सद्भाव और सौहार्द स्वतः ही विकसित हो जाता है। यह सब हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य का हिस्सा है और यही संविधान में एक व्यवस्था के रूप में हमें प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर हमें चेतना की स्वतंत्रता को सच्चे अर्थों में आत्मसात करना है। *(जगत फीचर्स)*

उत्तर भारत में पानी की बर्बादी का चरम

-प्रमोद भार्गव

हमारे देश में बीते 77 सालों के भीतर जिस तेजी से कृत्रिम, भौतिक और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढावा देने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, उतनी ही तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का या तो क्षरण हुआ है या उनकी उपलब्धता घटी है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है 'पानी'! 'जल ही जीवन है' की वास्तविकता से अवगत होने के बावजूद पानी की उपलब्धता भूमि के नीचे और ऊपर निरंतर कम होती रही है। नतीजतन भारत तेजी से भू-जल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्र पहले से ही इस स्थिति का सामना कर रहे हैं और कुछ में 2025 तक इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। यह संकट जल और खाद्यान दोनों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। हाल ही में जारी आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं का अध्ययन बताता हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते खाद्यान्न की खान कहे जाने वाले उत्तर भारत ने पिछले 20 साल में अपनी बहुमूल्य 450 घन किमी भूजल संपदा को बर्बाद कर दिया है। यह संपदा इतनी बड़ी है कि इससे देश के सबसे बड़े जलाशय इंदिरा सागर बांध को 37 बार लबालब भरा जा सकता है। इस भू-भाग में मानसूनी बारिश की कमी और सर्दियों में अपेक्षाकृत बढ़ते गर्म दिनों के चलते फसलों की सिंचाई के लिए भूजल की निर्भरता निरंतर बढ़ रही है। गोया, भूमि के भीतर का पानी लगातार घट रहा है। बरसाती जल को सहेजने के प्रयास चर्चा में तो बहुत रहते हैं, लेकिन नतीजे ढांक के तीन पात ही रहे हैं।

सुधारतियों ने अपने अध्ययन में पाया है कि समूचे उत्तर भारत में 1951-2021 की अवधि के दौरान बरसात के मौसम (जून से सितंबर) में बारिश में 8.5 प्रतिशत की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान इस क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। हेदराबाद स्थित राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) के सुधारतियों के दल ने अध्ययन में पाया है कि मानसून के दौरान कम बारिश होने और सर्दियों के दौरान तापमान बढ़ने के कारण सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ेगी और इसके कारण भूजल पुनर्भरण में कमी आएगी। नतीजतन उत्तर भारत में पहले से ही कम हो रहे भूजल संसाधन पर और अधिक दबाब बढ़ेगा। अध्ययन में पाया कि मानसून के दौरान बारिश कम होने से भूजल की अधिक जरूरत पड़ती है और सर्दियों में तापमान अधिक होने से मिट्टी अपेक्षाकृत शुष्क हो जाती है। फलस्वरूप बार-बार फसल को सिंचाई की जरूरत होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की कमी और बढ़ते तापमान के चलते भूजल पुनर्भरण में लगभग छह-12 प्रतिषत की कमी आने का अनुमान है। इसी कालखंड में सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ गई है। अतएव हमें अधिक दिनों तक धीमी बारिष की जरूरत है। परंतु विडंबना है कि बारिश पर अधिकार आदमी का नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 70 फीसदी जल का उपयोग खेती-किसानी के लिए होता है। दुनिया की छह पर्यावरणीय प्रणालियां जल का स्तर नीचे गिरने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते संकट के चरम बिंदु पर हैं। यदि हालात नहीं बदले तो जीव-जंतु विलुप्त होंगे, भू-जल घटेगा, हिमखंड पिघलेंगे और यदि अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता रहा तो असहनीय गरमी पड़ेगी। जो जीव-जगत के भविष्य के लिए चिंताजनक है। प्राकृतिक संपदा का दोहन और उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप विनाशकारी बदलाव लाएंगे। इसका पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु पद्धति और समग्र पर्यावरण पर गंभीर असर दिखेगा। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में पहले से ही भू-जल अधिकतम निचले स्तर पर है।

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भू-जल का इस्तेमाल करता है। यह अमेरिका और चीन दोनों के कुल प्रयोग से कहीं अधिक है। भारत का उत्तरी-पश्चिमी इलाका देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से अहम् है, लेकिन यहां तेजी से भू-जल का स्तर गिर रहा है। नतीजतन इसके दुष्परिणाम 2025 तक दिखना शुरू हो जाएंगे। जल स्रोत सूखने लग जाएंगे, जिसका असर खेती पर पड़ेगा। आजादी के दौरान प्रति व्यक्ति सालाना दर के हिसाब से पानी की उपलब्धता छह हजार घनमीटर थी, जो अब घटकर करीब डेढ़ हजार घनमीटर रह गई है। जिस तेजी से पानी के इस्तेमाल के लिए दबाव बढ़ रहा है और जिस बेरहमी से भूमि के नीचे के जल का दोहन नलकूपों से किया जा रहा है, उससे यह निश्चित-सा हो जाता है कि अगले कुछ साल बाद जल की उपलब्धता घटकर बमुश्किल सोलह सौ कि जगह हजार-ग्यारह सौ घनमीटर रह जाएगी। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) के अनुसंधानपरक अध्ययनों से साबित हुआ है कि भूमिगत जल का आवश्यकता से अधिक प्रयोग से भावी पीढ़ियों को कालांतर में जबरदस्त जल संकट का सामना करना होगा। नलकूपों के उत्खनन संबंधी जिन आंकड़ों को हमने 'क्रांति' की संज्ञा दी थी, दरअसल यह संज्ञा तबाही की पूर्व सूचना थी, जिसे हम नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। परंतु यह आशंका अब सच्चाई में बदलती नजर आ रही है।

खाद्यान्न सुलभता के आंकड़ों को पिछले 77 साल की एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, लेकिन इस खाद्यान्न उत्पादन के लिए जिस हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, उसके कारण नलकूपों की संख्या कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ी, फलस्वरूप उतनी ही तेजी से भूमिगत जल की उपलब्धता घटी केंन्द्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार नलकूप खुदाई की आमतौर से प्रचलित तकनीक गलत है। इस के लिए जमीन के भीतर तीस मीटर तक विधिवत सीलिंग होनी चाहिए ताकि जमीन की इस गहराई वाले हिस्से का पानी अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहे। इसके बाद नीचे की खुदाई जारी रखनी चाहिए। इस तकनीक के अपनाने से खर्च में 30 हजार रूपये की बढ़ोत्तरी जरूर होती है, लेकिन भू-जल स्तर में गिरावट नहीं आती। लेकिन इस तकनीक के अनुसार नलकूपों का उत्खनन देश में नहीं किया गया।

अध्ययन के अनुसार 1947 में कोई एक हजार के करीब नलकूप पूरे देश में थे, जिनकी संख्या अब कई करोड़ हो गई है। सस्ती अथवा मुफ्त बिजली देने से नलकूपों की संख्या में और बढ़ोत्तरी हुई है। पंजाब और मध्यप्रदेश की सरकारों ने किसानों को मुफ्त बिजली देकर नलकूप खनन को बेवजह प्रोत्साहित किया हुआ है। पंजाब के 12, हरियाणा के 3, मध्यप्रदेश के 15 जिलों से पानी ज्यादा निकाला जा रहा है, जबकि वर्षाजल से उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। गुजरात के मेहसाणा और और तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिलों में तो भूमिगत जल एकदम खत्म ही हो गया है। हरियाणा के कुरूक्षेत्र और महेन्द्रगढ़, मध्यप्रदेश के खण्डवा, खरगोन और भिण्ड जिलों में प्रति वर्ष जल की सतह आधा मीटर नीचे खिसक रही है। जल के नीचे उतर जाने से इस जल को ऊपर खींचने में ज्यादा बिजली खर्च हो रही है। जिन जल क्षेत्रों में पानी का अत्याधिक दोहन हो चुका है, वहां पानी खींचने के खर्च में 5000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। सिंचाई के लिए सौर्य ऊर्जा संयंत्रों पर छूट इनकी संख्या बढ़ा रही है।

नलकूपों से बड़ी मात्रा में खनन से कुओं के जलस्तर पर जबर्दस्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुओं की हालत यह है कि 75 प्रतिशत कुएं हर साल दिसम्बर माह में, 10 प्रतिशत जनवरी में और 10 प्रतिशत अप्रैल माह में सूख जाते हैं। एक ट्यूबवैल 5 से 10 कुओं का पानी सोख लेता है। जल विशेषज्ञ और पर्यावरणविद् भी अब मानने लगे हैं कि जल स्तर को नष्ट करने और जल धाराओं की गति अवरुद्ध करने में नलकूपों की मुख्य भूमिका रही है। नलकूपों के खनन में तेजी आने से पहले तक कुओं में लबालब पानी रहता था, लेकिन सफल नलकूपों की पूरी एक श्रृंखला तैयार होने के बाद कुएं समय से पहले सूखने लगे हैं। भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों का इस सिलसिले में कहना है कि भूमि में 210 से लेकर 330 फीट तक छेद (बोर) कर दिए जाने से धरती की परतों में बह रही जलधाराएं नीचे चली जाती हैं। इससे जलस्तर भी नीचे चला जाता है। नलकूपों का खनन करने वाली आधुनिक मशीनों के चलने में धरती की परतों का बहुत बड़ा क्षेत्र प्रकंपित होता है। इससे अविरल बह रही जलधाराओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नतीजतन सैंकड़ों साल की प्रक्रिया से अस्तित्व में आने वाली जलधाराओं की संरचना अस्त-व्यस्त हो जाती है। जबकि जलस्तर को स्थिर बनाए रखने में यही धाराएं सहायक रहती हैं। अंधाधुंध नलकूपों के गहरीकरण पर तत्काल नियंत्रण लगाकर इसके वैकल्पिक उपाय नहीं तलाशे गए तो कालांतर में जबर्दस्त संकट जल की कमी और जल प्रदूषण का होगा। इस समस्या के निराकरण के सार्थक उपाय बड़ी मात्रा में पारंपरिक जलग्रहण के भण्डार तैयार करना है। पारंपरिक मानते हुये जलग्रहण की इन तकनीकों की हमने पिछले 77 सालों में घोर उपेक्षा की है। (जगत फीचर्स)

निरर्थक कानूनों का बोझ

सत्ता और समाज पर नजरिया

-जयंत वर्मा

पिछले अंक से आगे

केन्द्र सरकार ने अब तक कुल 15 विधि आयोग बनाये हैं जिनका प्राथमिक कार्य पुराने कानूनों की समीक्षा औरउनके निरस्तीकरण का है। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवनरेड्डी वर्तमान पंद्रहवें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इस आयोग को वर्तमान में जो दायित्व सौंपा गया है उनमें (जनहित की बजाय आर्थिक उदारीकरण के रास्ते में आने वाले रूकावटी कानून की पहचान करना। (गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा। (न्यायिक प्रशासन की समीक्षा कर समयानुकूल परिवर्तन की अनुशंसा। (संविधान की उद्देश्यिका और राज्य के लिए नीति के निदेशक तत्वों के अनुरूप कानूनों को बदलने के सुझाव देना। (कानूनी विसंगतियों को दूर करने के सुझाव देना आदि। इस आयोग अनेक प्रतिवेदन भी दिये हैं किन्तु उन्हें पढ़कर तदनुसार कार्यवाही के प्रति गंभीरता का वर्तमान में अभाव है। राज्यों में तो इस प्रकार का कोई अभ्यास करने का विचार ही नहीं है। विधायिका को विधायी कार्यों के प्रति सजग बनाने और संविधान के प्रकाश में विधेयकों पर बहस करवाने की बुनियादी ज़रूरत है, तभी जनहितकारी कानूनी ढांचा बनेगा और जनता को राहत मिलेगी।

जिला सरकारें...!

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोबारा जनादेश मिलने के बाद राजनीति से लोकनीति का संकल्प लिया और प्रशासन तंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण का एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। 1 अप्रैल 1999 से मध्यप्रदेश में 45 जिला सरकारें काम करने लगी हैं। वस्तुतः सरकार से हमारा अभिप्राय यह होता है कि वह जनता द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से नियुक्त की जाती है। जन प्रतिनिधियों की विधानसभा के प्रति वह उत्तरदायी होती है। जन आकांक्षाओं को मूर्तरूप देने वह नियम और कानून बनाने में सक्षम होती है। राजकोष को संचालित करने के लिए वह विधानसभा से बजट पारित करवाती है तथा तदनुसार खर्च करती है। राज्य का मंत्रिमंडल सरकार होती है जो जनभावना का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य के विभिन्न विभागों के सचिव सरकार के सलाहकार होते हैं जो जनभावनाओं को अमली जामा पहनाने में संवैधानिक और कानूनी पक्ष को देखने तथा राज्यपाल की संविधान और विधि के परिरक्षण की शपथ को भंग नहीं होने देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। राज्यपाल अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सहायता लेता है क्योंकि मंत्रिपरिषद जन-भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। सविधान के अन्तर्गत कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद दे तो राज्यपाल उस सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते। क्योंकि ऐसा करके वे अपनी शपथ का उल्लंघन करेंगे। राज्य की मंत्रिपरिषद भी बिना किसी भय पक्षपात अनुराग या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने के नीयत से राज्यपाल को उनके संवैधानिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए कार्य करेगी, ऐसा प्रावधान रखा गया है।

सरकार की कार्यपालिका के अलावा विधायी शक्ति न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और आपात शक्तियां भी राज्यपाल के पास होतीं हैं और इस प्रकार संविधान के तहत सरकार का काम चलता है। राज्यपाल यह भी शपथ लेते हैं कि वे राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे अर्थात् मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के अधिकारों के अन्तर्गत कार्य करने वाली नौकरशाही का यह संवैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके सभी कार्यों का बुनियादी उद्देश्य जनता की सेवा और कल्याण हो। संवैधानिक प्रावधानों की इस पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद यदि भय पक्षपात अनुराग या द्वेष से कोई भी कार्य राज्यपाल से करवाती है अथवा जनता की सेवा और कल्याण की भावना के विरूद्ध यदि कोई कार्य राज्यपाल से करवाती है तो मंत्रिपरिषद का ऐसा कृत्य असंवैधानिक होता है और असंवैधानिक कृत्य करने वाली सरकार को बर्खास्त कर देने पर ही संविधान की रक्षा संभव है। सरकार की संविधान के प्रति जवाबदेही जिस दिन इस तरीके से कायम कर दी जावेगी, उस दिन जनता की समस्याएं हल होने लगेंगी। प्रशासन को भी अपने कर्त्तव्यों के प्रति गंभीर और जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकेगा तथा राजधानी में ही रहकर सरकार जन-कल्याण कर सकेगी। संविधान की मनगढ़ंत व्याख्या करने वाली सरकारें जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर पातीं हैं और जन-असंतोष को समाप्त करने के लिए नए-नए प्रयोगों की जरूरत पड़ती है। क्रमशः

क्रमशः

(लेखक एवं विचारक)

शादियों पर दिखावा बंद हो

-रघु ठाकुर

मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका के लगभग 93वें दिन के विवाह पर्व का समापन हो गया और बकाया देश की तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे जैसे समाचार पत्रों के पाठकों को कुछ सुकून मिला। वरना तीन माह से कब मंगनी हुई, कब फलनी हुई, कहाँ इटली में प्रीवेडिंग हुई, द्वीप किराये पर लिये, कितने हवाई जहाज, कितने बम्बई के फिल्मी दुनिया के नचईये-गबईये शामिल हुए, कितने हजार करोड़ की शादी हुई, इन्हीं उबाई वाली खबरों से मीडिया भरा पड़ा था। विवाह के खर्च के बारे में लोगों के अलग-अलग अनुमान हैं जो हजार करोड़ से लेकर 5-10 हजार करोड़ तक के खर्च बताते हैं। यह अनुमान स्वाभाविक है। क्योंकि इटली में पूरा द्वीप कई दिनों तक किराये पर लेना, विवाह के अंतिम दिन समारोह में आये मेहमानों को दो-दो करोड़ के गिफ्ट देना यह सामान्य घटना नहीं है और खर्चों के 5000 करोड़ के अनुमान को सही ठहराती है।

ऐसा लग रहा है कि जैसे अंबानी के थुलथुल बेटे की शादी कोई राष्ट्रीय पर्व बन गया हो और जिसका खर्च कहने को अंबानी कर रहे हों परंतु देश के आम नागरिक को इसमें अपना हिस्सा अदा करना पड़ रहा है। विवाह के आयोजनों के दौर में अंबानी ने जियो फोन की दरों को बढ़ा दिया और एक प्रकार से देश के जियो के ग्राहकों के ऊपर विवाह टैक्स लगा दिया। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री का दोस्त वही हो सकता है जो आपदा में अवसर खोज लेता हो। इस शादी से और उसकी चर्चा से देश में कई प्रकार की मनोविकृतियां पैदा हुई।

आम आदमी ऐसे भारी महंगी शादियां जिसमें तथाकथित वीवीआईपी या सेलिब्रिटीश शामिल हों के प्रति लालायित आकर्षित होता है। और इसका परिणाम यह होगा कि ये और उनके बच्चे अपनी शादियों में इस दिखावे के लिये क्षमता से अधिक खर्च करेंगे। मुझे स्मरण है कि लगभग 35-36 वर्ष पहले, जब स्व. माधवराव सिंधिया की बेटी की शादी का आयोजन ग्वालियर में हुआ था तो हेलीकाप्टर से फूल बरसाये गये थे। मैं व मेरे उस समय के मित्र स्व. शरद यादव उस शादी के कुछ दिनों के बाद ग्वालियर की यात्रा पर थे तथा हमारे समाजवादी साथी स्व. विष्णुदत्त तिवारी के मकान पर बैठे थे, तब एक गाँव का किसान मिलने के लिये आया था जो अंचल की पिछड़ी जाति गुर्जर समाज से था और उसने हम लोगों से पूछा कि हैलीकाप्टर का किराया कितना लगता है। हम लोगों ने बताया कि बहुत पैसा लगता है और क्यों जानना चाहते हो तो उसने बताया कि मैं मेरी बेटी की शादी में हेलीकाप्टर से फूल बरसाना चाहता हूं। हमने उससे पूछा कि इतना पैसा तुम कहां से लाओगे? तो उसने उत्तर दिया कि 10 एकड़ जमीन बेच दूंगा पर हेलीकाप्टर से फूल बरसाऊँगा। ऐसे खर्चीले व दिखावटी आयोजन का आमजन के मानस पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है यह इस घटना से समझा जा सकता है। और उसके बाद पिछले वर्षों में अनेकों ऐसे समाचार मीडिया में आये हैं जहाँ गाँव के किसान और पिछड़ी जाति के लोगों ने फूल बरसाने या वर-वधु की विदाई के लिए हेलीकाप्टर किराये पर लिये।

अंबानी के इस वैभवपूर्ण विवाह ने जहां एक तरफ आमजन के मानस में भोगविलास, दिखावा, फिजूलखर्ची के कीटाणु पैदा कर दिल व दिमाग को विकृत्त किया है, उसके साथ ही बाजार के लिये नये द्वार भी खोल दिये हैं। इन सब दिखावों के ऊपर जो पैसा खर्च होगा अंततः वह बाजार में ही जायेगा। और इसलिये शायद मीडिया ने इन खबरों को आकर्षक बनाकर परोसा है क्योंकि मीडिया के मालिक भी वही उद्योगपति व व्यापारी हैं। मीडिया अगर एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार के विवाह में 5-10 लाख रुपये खर्च करता होगा तो अपवाद छोड़ दें तो वह अब अपनी क्षमता से बाहर जाकर भले ही उसे अचल संपत्ति बेचना पड़े, कर्ज लेना पड़े, पर वह 20-30 लाख रुपये खर्च करेगा। उसके बच्चे उसे बाध्य करेंगे।

उदाहरण के लिये मान लीजिये एक वर्ष में देश में 1 करोड़ शादियां होती हों और उनमें से 50-60 लाख शादियां मध्यमवर्गीय परिवारों की हो तो देश के बाजार को आसानी से 5-10 लाख करोड़ का व्यापार मिल जायेगा। मनोविकृत्तियों को बिगाड़कर, भोग और जलसे और दिखावे की मानसिकता को तैयार कर, पैसा कमाने के कई प्रकार के प्रयोग पिछले वर्षों से मीडिया ने शुरू कराये हैं। विवाह की वर्षगांठ, विवाह के 25 साल, 50 साल और इन्हें एक बार फिर से नये विवाह के समान बारात और जुलस से लेकर सभी नाटकीय पुनरावृत्ति शुरू कराई गई। जिन पर 10-20 लाख का खर्च तो मामूली तौर पर होता है। याने अब ऐसा समय आयेगा जिसमें जितनी शादीयां होंगी उनसे ज्यादा शादीयों की वर्षगांठ होगी। जन्म दिवस के उत्सव, मुंडन का उत्सव और न जाने कितने प्रकार के उत्सव शुरू करा दिये गये जिनमें दिखावे व प्रचार ने मध्यमवर्ग को उलझा दिया। इस उत्सवधर्मिता ने एक और लाभ व्यापार जगत को पहुंचाया है वह यह है कि मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय वर्ग अपने सारे, सामाजिक सरोकारों को भूल जाता है व केवल इन समारोहों के विजर्सन, उनमें शिरकत करने में फँसा रहता है।

अगर उसके जीवन के कालखण्ड का सामान्य अध्ययन किया जाये तो साल के लगभग 100 दिन, समाज के उच्च व मध्यम वर्ग के लोग विवाह, विवाह की वर्षगांठ, जन्मदिन, कथा और भण्डारे, तीर्थदर्शन आदि पर खर्च करता है और बकाया समय अपने पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए ड्यूटी पर जाता है। याने वह आम समाज से शारारिक और मानसिक रूप से कट जाता है तथा अपने समाज या देश के बारे में सोचने-विचारने, उसमें सहभागिता करने का न समय उसके पास होता है और न ही उसका मन होता है। अंबानी के इस विवाह का निमंत्रण उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मंत्रियों और विरोधी दलों के नेताओं को भी दिया था, जिनकी देर सवेर सत्ता में आने की संभावनायें हैं या जिनके उनके साथ राजनीति व व्यापारिक रिश्ते हैं जो संसद या विधानसभा के माध्यम से उन्हें लाभ या हानि पहुँचा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो उनके समारोह में न केवल सम्मिलित हुये बल्कि मीडिया के अनुसार 2 घंटे 40 मिनिट वहाँ रहे। मैं मान सकता हूं कि चूंकि दोनों गुजरात के हैं और प्रधानमंत्री की राजनीति व धीरूभाई अंबानी के परिवार में गहरा रिश्ता होगा, परंतु एक देश का प्रधानमंत्री एक उद्योगपति के विवाह पर्व में पौने 3 घंटे रहे क्या यह देश के प्रशासन तंत्र को खुला संदेश नहीं है? और सत्ता प्रतिष्ठान व उद्योग प्रतिष्ठान के गहरे रिश्तों का खुलासा नहीं करता। फिर प्रधानमंत्री जी की इस विवाह यात्रा का खर्च किसने उठाया? प्रधानमंत्री की यात्रा पर पर खर्च, विमान, सुरक्षा आदि मिलाकर करोड़ों में होता हैं। क्या प्रधानमंत्री ने यह खर्च निजी कोष से उठाया है? क्या यह खर्च अंबानी समूह ने उठाया है? या देश की गरीब जनता को भोग और जलसों के लिये, प्रेरित करने का खर्च भी सरकारी खजाने याने जनता ने उठाया है? अगर प्रधानमंत्री जी ने यह खर्च स्वतरू उठाया हो या अभी भी इसकी राशि जमा कर दें तो कम से कम यह उनकी नैतिकता होगी परंतु यह होगा नहीं। मुकेश अंबानी ने कांग्रेस के संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी को भी निमंत्रण दिया था और मीडिया के अनुसार वह 1 घंटे उनके साथ रहे। एक निमंत्रण के देने में 1 घंटे का समय कुछ आश्चर्यजनक भी है और कुछ राजनैतिक संदेश व संभावनायें भी पैदा करता है। गुजरात के एक राजनेता देवेन्द्र यादव ने तो आरोप ही लगाया है कि अंबानी ने कांग्रेस के साथ कुछ डील कर ली है और उसी का एक हिस्सा है कि राहुल गांधी ने (यद्यपि वे शादी में नहीं गये थे या पता नहीं उन्हें निमंत्रित किया गया था या नहीं) गुजरात में जाकर कहा कि अब गुजरात में सरकार कांग्रेस की आयेगी। उनकी यह असामयिक घोषणा कुछ चौंकाने वाली तो है। क्योंकि उद्योग जगत ईश्वर प्रदत्त दोनों हाथों से बाँटता है। एक से सत्ता के लिये और दूसरे से सत्ता के संभावितों के लिये। यद्यपि व्यक्तिक निमंत्रण पत्र इंडिया गठबंधन के बड़े हिस्सेदार ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे तो इस विवाह में शामिल हुये ही, साथ ही लालूप्रसाद तो संपूर्ण परिवार की फौज के साथ शामिल हुये। अगर इसे गणित से तौला जाये तो इंडिया गठबंधन का बहुमत विवाह समारोह में शामिल हुआ। मेरी राय में ऐसी शादियों पर देश में रोक लगनी चाहिये जो अमीरी व विलासिता का नग्न प्रदर्शन करती है। अंबानी के ऊपर इस विलासिता के खर्च के लिये विशेष टैक्स लगाया जाना चाहिये और वह दिन सुखद दिन होगा जब मीडिया स्वतः अपने लाभ व व्यापार का मोह छोड़कर ऐसी शादियों को प्रचारित करना बंद करेगा। वरना अभी तो देश में एक सुनियोजित अभियान चल रहा है कि हर व्यक्ति, हर युवा के मन में अंबानी पैदा कर दिया जाये। जो संपत्ति से भले ही अंबानी नहीं हो पर दिमागी तौर पर उस सभ्यता का पिछलग्गू होगा व विषमता के लिये अपना आदर्श मानेगा।

सामाजिक संगठनों को चाहिये कि ये शादियों की इन परंपराओं, दिखावों, फिजूलखर्ची और बेहतर हो कि रात्रि की शादियों पर रोक लगायें। आजकल एक प्री-वेडिंग नाम का चलन शुरू हुआ है। यह एक प्रकार से शादी पूर्व शादी या शादी के समान ही खर्चीली परंपरा शुरू की गई है। इस प्री-वेडिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं और मानसिक तौर पर पूंजीवाद के बीज डाले जा रहे हैं। मेरे एक मित्र ने बताया कि प्रीवेडिंग की उनकी बेटी की जिद के कारण उन्हें शादी के अनुमानित खर्च में लगभग दो गुना खर्च करना पड़ा और उन्होंने अपनी एक एकड़ जमीन बेचकर उसे चुकाया। यह दुखद है कि समाजवाद व लोहिया का नाम लेने वाले कुछ लोग भी ऐसी शादियों में शामिल होकर या उनकी नकल कर समाजवादी आंदोलन को एवं समता के सघर्ष को कमजोर कर रहे हैं। राजनीति मात्र सत्ता का खेल नहीं है बल्कि समाज के मानसिक बदलाव, राजनैतिक बदलाव व सांस्कृतिक क्रांति का भी माध्यम होती है। जो गांधी, लोहिया व समाजवाद को मानते हैं अगर वह इतना भी आत्म निर्णय कर लें कि न ऐसे किसी दिखावटी आयोजन को करेंगे न उसमें शामिल होंगे तो यह भी एक अच्छी शुरूआत हो सकती है।

(जगत फीचर्स)

कलम के सिपाही...

आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे राजेन्द्र प्रसाद

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। वह एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात विधिवेत्ता, वाकपटु सांसद, सुयोग्य प्रशासक और श्रेष्ठ राजनेता होने के साथ-साथ महान मानवतावादी थे। महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी होने के साथ-साथ वह भारतीय संस्कृति सभी उत्तम विशेषताओं से युक्त थे। संविधान सभा के अध्यक्ष और तत्पश्ताच् लगातार दो कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्र की दशा-दिशा निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे राष्ट्रीय जीवन तथा शासन व्यवस्था पर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जिन्हें प्यार से राजेन बाबू कहा जाता था का जन्म 3 दिसंबर 1884 कोबिहार के सारण में हुआ था। परिवार के पास पर्याप्त भू-सम्पदा थी। उन्होंने वर्ष 1902 में प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1915 में प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से मास्टर इन लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1916 में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपना कानूनी कॅरियर शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। जब गांधीजी स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिये बिहार के चंपारण ज़िले में एक तथ्यान्वेषी मिशन पर थे, तब उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने का आह्वान किया। गांधीजी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को परिवर्तित किया, सबसे महत्त्वपूर्ण जाति और अस्पृश्यता संबंधी विचार था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए इसके उपरांत उनका संपूर्ण जीवनदर्शन ही बदल गया। वर्ष 1918 के रॉलेट एक्ट और वर्ष 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने राजेंद्र प्रसाद को गांधीजी के और करीब ला दिया। डॉ. प्रसाद ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और वर्ष 1921 में पटना में एक नेशनल कॉलेज शुरु किया।

मार्च 1930 में, गांधीजी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। डॉ. प्रसाद के नेतृत्त्व में बिहार के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह चलाया गया। नमक बनाते समय स्वयंसेवकों के अनेक दलों की गिरफ्तारी हुई। तब उन्होंने और स्वयंसेवकों को बुलाया। जनमत ने सरकार को पुलिस को वापस लेने और स्वयंसेवकों को नमक बनाने की अनुमति देने के लिये मज़बूर किया। इसके बाद उन्होंने फंड जुटाने के लिये तैयार किये गए नमक बेच दिया था। उन्हें छह महीने के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी।

वह आधिकारिक तौर पर वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कान्ग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद से के इस्तीफे के बाद वे दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1946 में, वे पंडित जवाहरलाल नेहरु की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और "अधिक अन्न उगाओ" का नारा दिया। जुलाई 1946 में, जब भारत के संविधान को बनाने के लिये संविधान सभा की स्थापना की गई, तो उन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया। आजादी के ढाई साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि हुई और उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 1962 में, राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्ष के बाद, डॉ. प्रसाद सेवानिवृत्त हुए और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्ति में अपने जीवन के अंतिम कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 फरवरी, 1963 को उनका निधन हो गया।

प्रभात झाः लोक संग्रह और संघर्ष से बनी शख्सियत

-प्रो. संजय द्विवेदी

स्मृति लेख

यह नवें दशक के बेहद चमकीले दिन थे। उदारीकरण और भूमंडलीकरण जिंदगी में प्रवेश कर रहे थे। दुनिया और राजनीति तेजी से बदल रहे थी। उन्हीं दिनों मैं छात्र आंदोलनों से होते हुए दुनिया बदलने की तलब से भोपाल में पत्रकारिता की पढ़ाई करने आया था। एक दिन श्री प्रभात झा जी अचानक सामने थे, बताया गया कि वे पत्रकार रहे हैं और भाजपा का मीडिया देखते हैं। इस तरह एक शानदार इंसान, दोस्तबाज, तेज हंसी हंसने वाले, बेहद खुले दिलवाले झा साहब हमारी जिंदगी में आ गए। मेरे जैसे नये-नवेले पत्रकार के लिए यह बड़ी बात थी कि जब उन्होंने कहा कि" तुम स्वदेश में हो, मैं भी स्वदेश में रह चुका हूं।" सच एक पत्रकार और संवाददाता के रूप में ग्वालियर में उन्होंने जो पारी खेली वह आज भी लोगों के जेहन में हैं। एक संवाददाता कैसे जनप्रिय हो सकता है, वे इसके उदाहरण हैं। रचना, सृजन, संघर्ष और लोक संग्रह से उन्होंने जो महापरिवार बनाया मैं भी उसका एक सदस्य था।

उत्साह, ऊर्जा और युवा पत्रकारों को प्रोत्साहित कर दुनिया के सामने ला खड़े करने वाला प्रभात जी का स्वभाव उन्हें खास बनाता था। अब उनका पर्याय नहीं है। वे अपने ढंग के अकेले राजनेता थे, जिनका पत्रकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों से लेकर पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं तक आत्मीय संपर्क था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। फिर उसकी विचारधारा से जुड़े अखबार में रहे और बाद में भाजपा को समर्पित हो गये। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक उनकी यात्रा उनका एकांगी परिचय है। वे विलक्षण संगठनकर्ता, अप्रतिम वक्ता और इन सबसे बढ़कर बेहद उदार व्यक्ति थे। उनके जीवन में कहीं जड़ता और कट्टरता नहीं थी। वे समावेशी उदार हिंदू मन का ही प्रतीक थे। उनका न होना मेरी व्यक्तिगत क्षति है। वे मेरे संरक्षक, मार्गदर्शक और सलाहकार बने रहे। उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन ने मेरे जैसे न जाने कितने युवाओं को प्रेरित किया।

उनके निधन से समाज जीवन में जो रिक्तता बनी है, उसे भर पाना कठिन है। छात्र जीवन से ही उनका मेरे कंधे पर जो हाथ था, वह कभी हटा नहीं। भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, मुंबई मेरी पत्रकारीय यात्रा के पड़ाव रहे, प्रभात जी हर जगह मेरे साथ रहे। वे आते और उससे पहले उनका फोन आता। उनमें दुर्लभ गुरूत्वाकर्षण था। उनके पास बैठना और उन्हें सुनने का सुख भी विरल था। किस्सों की वे खान थे। भाजपा की राजनीति और उसकी भावधारा को मैं जितना समझ पाया उसमें श्री प्रभात झा और स्व.लखीराम अग्रवाल का बड़ा योगदान है। भाजपा की अंर्तकथाएं सुनाते फिर हिदायत भी देते, ये छापने के लिए नहीं, तुम्हारी जानकारी और समझ के लिए है।

मुझे नहीं पता कि प्रभात जी पत्रकारिता में ही रहते तो क्या होते। किंतु भाजपा में रहकर उन्होंने 'विचार' के लिए जगह बनाकर प्रकाशन, लेखन और मीडिया के पक्ष को बहुत मजबूत किया। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की जमीन पर भाजपा के विचार को मीडिया और बौद्धिक वर्ग में उन्होंने लोकस्वीकृति दिलाई। वे 'कमल संदेश' जैसे भाजपा के राष्ट्रीय मुखपत्र के वर्षों संपादक रहे। राज्यों में भाजपा की पत्रिकाएं और प्रकाशन ठीक निकलें, ये उनकी चिंता के मुख्य विषय थे। आमतौर पर राजनेता जिन बौद्धिक विषयों को अलक्षित रखते थे, प्रभात जी उन विषयों पर सजग रहते। वे उन कुछ लोगों में थे जिनका हर दल और विचारधारा से जुड़े लोगों से संवाद था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था "अपने कार्यक्रमों में सभी को बुलाएं, तभी आनंद आता है। एक ही विचार के वक्ताओं के बीच एकालाप ही होता है, संवाद संभव नहीं।" उन्होंने मेरी किताब 'मीडिया नया दौर नयी चुनौतियां' का लोकार्पण एक भव्य समारोह में किया। जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो.बीके कुठियाला, टीवी पत्रकार और संपादक रविकांत मित्तल भी उपस्थित थे। दिल्ली के अनेक मंचों पर मुझे उनका सान्निध्य मिला। उनका साथ एक ऐसी छाया रहा, जिससे वंचित होकर उसका अहसास अब बहुत गहरा हो गया है। वे हमारे जैसे तमाम युवाओं की जिंदगी में सपने जगाने वाले नायक थे। हम छोटे शहरों, गांवों से आए लोगों को वे बड़ा आसमान दिखाकर उड़ान के लिए छोड़ देते थे।

उन्होंने तमाम ऐसी प्रतिभाओं को खोजा, उन्हें संगठन में प्रवक्ता, संपादक, मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम सांगठनिक पदों तक पहुंचने में मदद की। एक समय भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के नाते वे बहुत ताकतवर थे। अध्यक्ष राजनाथ सिंह (अब रक्षा मंत्री) उन पर बहुत भरोसा करते थे। प्रभात जी ने इस समय का उपयोग युवाओं को जोड़ने में किया। मैं नाम गिनाकर न लेख को बोझिल बनाना चाहता हूं, न उन व्यक्तियों को धर्म संकट में डालना चाहता हूं, जो आज बहुत बड़े हो चुके हैं। भाजपा का आज स्वर्ण युग है, संसाधन, कार्यकर्ता आधार बहुत विस्तृत हो गया है। किंतु प्रभात जी बीजेपी के 'ओल्ड स्कूल' में ही बने रहे। जहां पार्टी परिवार की तरह चलती थी और व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क को महत्व दिया जाता था। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के अनेक राज्यों के कार्यकर्ता, पत्रकार,समाज के विविध क्षेत्रों में सक्रिय लोग उनसे बेहिचक मिलते थे। इस सबके बीच उन्होंने अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मैंने उन्हें दीनदयाल परिसर के एक छोटे कक्ष में रहते देखा है। परिवार ग्वालियर में ,खुद भोपाल में एकाकी जीवन जीते हुए। यहां भी दरवाजे सबके लिए हर समय खुले थे, जब अध्यक्ष बने तब भी। दिनचर्या पर उनका नियंत्रण नहीं था, क्योंकि पत्रकारिता में भी कोई दिनचर्या नहीं होती। मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जिस तरह तूफानी प्रवास किया, उसने कार्यकर्ताओं को भले खुश किया। राजपुत्रों को उनकी सक्रियता अच्छी नहीं लगी। वे षड्यंत्र के शिकार तो हुए ही, अपना स्वास्थ्य और बिगाड़ बैठे। उनका पिंड 'पत्रकार' का था, किंतु वे 'जननेता' दिखना चाहते थे। इससे उन्होंने खुद का तो नुकसान किया ही, दल में भी विरोधी खड़े किये। बावजूद इसके वे मैदान छोड़कर भागने वालों में नहीं थे। डटे रहे और अखबारों में अपनी टिप्पणियों से रौशनी बिखेरते रहे। आज जब परिवार जैसी पार्टी को कंपनी की तरह चलाने की कोशिशें हो रही हैं, तब प्रभात झा जैसे व्यक्ति की याद बहुत स्वाभाविक और मार्मिक हो उठती है। उनकी पावन स्मृति को शत्-शत् नमन। भावभीनी श्रद्धांजलि।

(लेखक भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक हैं)

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। ***संपादक : विजया पाठक।***
RNI-MPBIL/2011/39805 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)*